



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 218-2023/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, DECEMBER 13, 2023 (AGRAHAYANA 22, 1945 SAKA)

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

अधिसूचना

दिनांक 13 दिसम्बर, 2023

संख्या 09/119/2023-4क II.- हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 16) की धारा 149 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 87 की उप-धारा (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग (समितियाँ), अधिसूचना संख्या का०आ० 85/ह०अ० 16/1994/धा० 87/2013, दिनांक 11 अक्टूबर, 2013 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग (समितियाँ), अधिसूचना संख्या का०आ० 85/ह०अ० 16/1994/धा० 87/2013, दिनांक 11 अक्टूबर, 2013 में, पैरा 3 में, उप-पैरा (viii) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(viii) गाँवों के लाल डोरा के भीतर स्थित आवासीय सम्पत्तियों को नगर निगमों की सीमाओं में शामिल होने की तिथि से पांच वर्ष तक प्रथम अप्रैल, 2020 से सम्पत्ति कर पर सौ प्रतिशत की छूट अनुज्ञेय होगी।"

विकास गुप्ता,
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT

Notification

The 13th December, 2023

No. 09/119/2023-4CII.— In exercise of the powers conferred under sub-section (3) of section 87 read with sub-section (1) of section 149 of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 (16 of 1994), the Governor of Haryana hereby makes the following amendment in the Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees), notification No. S.O. 85/H.A.16/1994/S. 87/2013, dated the 11th October, 2013, namely :-

Amendment

In the Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees), notification No. S.O. 85/H.A.16/1994/S. 87/2013, dated the 11th October, 2013, in para 3, for sub-para (viii), the following sub-para shall be substituted, namely:-

“(viii) A rebate of 100% on Property Tax with effect from the 1st April, 2020 shall be allowed to the residential properties situated within Lal Dora of Villages for five years from the date of their inclusion in the limits of Municipal Corporations.”.

VIKAS GUPTA,
Commissioner and Secretary to Government Haryana,
Urban Local Bodies Department.